India's outstanding liabilities to the International Monetary Fund (IMF) as at the end of March 1997 and end of March 1998 amounted to US$ 1,313 million (SDR 996.62 million) and US$ 664 million (SDR 497.33 million) respectively.

During the last two years i.e. 1996-97 and 1997-98 there were no purchases from the IMF. Various payments were effected to the IMF in the form of repurchases and payment of charges during these two years amounting to US$ 1,101 million (SDR 765 million) and US$ 701 million (SDR 513 million), respectively.

मध्य प्रदेश में लेखा-परीक्षा की गति

632. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के आयकर विभाग में लेखा-परीक्षा कार्य की गति बहुत धीमी है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) प्रदेश के आयकर विभाग में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें दस वर्ष पूर्व छापे के दौरान जब्त की गई लेखा बहियां अब तक नहीं लौटाई गई हैं;

(ग) इतने लम्बे समय से इन लेखा बहियों को विभाग द्वारा अपने पास रखने के क्या कारण हैं और ये लेखा बहियां कब तक संबद्ध व्यक्तियों को लौटा दी जाएंगी; और

(घ) मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ऐसे कुल कितने मामले हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दन): (क) मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षा कार्य उचित एवं संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश क्षेत्र में 254 ऐसे मामले हैं जिनमें दस वर्ष पूर्व मारे गए छापों के दौरान लेखा बहियों को जब्त किया गया था जिन्हें अभी तक वापस नहीं लौटाया गया है।

(ग) तलाश और अभिग्रहण मामलों में कर निर्धारण कार्यवाहियों को पूरा करने हेतु लेखा-बहियों की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात् उन्हें अभियोजन कार्रवाईयां शुरू करने तथा उन्हें अन्तिम रूप दिए जाने सहित आगे की विधिक कार्रवाईयों के दौरान भी मंगाया जा सकता है। इन कार्रवाईयों के अनिर्णीत होने के कारण लेखा-बहियों को लौटाया नहीं गया है।

(घ) विदिशा जिले में अर्थात श्री ओंकार लाल, मार्फत लक्ष्मीनारायन ओंकार लाल विदिशा (म०प्र०) का ही एक ऐसा मामला है।

Measures Contemplated by Public Sector Banks for Vidarbha Farmers

633. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the role played by Public Sector Banks particularly by the leading banks in Vidarbha region of Maharashtra to ameliorate the financial condition of more than two million farmers whose crops were damaged by natural calamities recently leading to suicides by many farmers, details thereof;

(b) how many farmers were given loans by each of the banks to overcome their debt traps during the last six months in the region bank-wise; and

(c) what other measures are being contemplated by banks to provide easy loans to farmers of Vidarbha?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) and (c) As reported by Reserve Bank of India (RBI), standing guidelines already exist regarding extension of relief measures by banks to borrowers in the areas affected by natural calamities. These guidelines enable banks to take uniform and concerted action expeditiously particularly to provide financial assistance to farmers affected by natural calamity. These guidelines envisage, inter-alia, conversion of short term production loans into medium term loans, moratorium on recovery during the year of occurrence of the natural calamity, reschedulement/postponement of existing term loan instalments, immediate provision of need-based crop loans/working capital loans, extension of consumption loans upto Rs. 1,000/- and non-charging of penal/compound interest on current dues/rescheduled loans.